अंक 19, संख्या 4

अक्टूबर – दिसम्बर, 2019

# जनसंदेश

भारतीय संसदीय संस्थान – जनसंख्या एवं विकास का त्रैमासिक न्यूज़लैटर

## ICPD +25 के नैरोबी सम्मेलन के पश्चात IAPPD की स्थायी समिति की सांसदों के साथ बैठक

यूथबॉल अभियानः युवा अपने स्वास्थ्य के लिए क्या चाहते हैं
5 दिसंबर, 2019, नई दिल्ली

12–14 नवंबर, 2019 को जनसंख्या और विकास पर 25 साल के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों पर नैरोबी सम्मेलन में, जिसमें भारत भी एक हस्ताक्षरकर्ता है, का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में राजनीतिक नेताओं, नौकरशाहों और नागरिक समाज के सदस्यों द्वारा भाग लिया गया।

जनसंख्या और विकास के मुद्दों पर जागरूकता पैदा करने और एड्वोकेसी हेतु भारतीय संसदीय संस्थानः जनसंख्या एवं विकास (IAPPD) द्वारा हमेशा से सांसदों के साथ जनसंख्या और विकास के मुद्दों पर जानकारी साझा करने और प्रयास किये जाते रहे हैं। उसी के अनुसरण में, IAPPD की स्थायी समिति की एक बैठक 5 दिसंबर, 2019 को दिल्ली में आयोजित की गई।

बैठक के मुख्य अतिथि राज्य सभा के माननीय उपसभापति श्री हरिवंश नारायण सिंह, पूर्व उपसभापति प्रो. पी.जे. कुरियन और राज्य सभा सदस्या सुश्री विप्लव ठाकुर सहित लगभग 21 सांसद उपस्थित थे।

पृष्ठ 4 पर जारी .....

श्री. मनमोहन शर्मा माननीय सांसदों का स्वागत करते हुए।

## एक टी.बी. मुक्त पंजाब निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए अमृतसर और जालंधर में कार्यशालाएँ

20 एवं 23 दिसंबर, 2019

20 और 23 दिसंबर, 2019 को IAPPD द्वारा पंजाब के अमृतसर और जालंधर ज़िलों में टी.बी. मुक्त पंजाब की दिशा में प्रयास विषय पर निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए दो कार्यशालाएँ आयोजित की गईं।

अमृतसर कार्यशाला का उद्घाटन श्री ओ.पी. सोनी, माननीय कैबिनेट मंत्री पंजाब द्वारा एवं जालंधर कार्यशाला का उद्घाटन सांसद चौधरी संतोख सिंह द्वारा किया गया।

बड़ी संख्या में चुने गए प्रतिनिधियों ने दोनों कार्यशालाओं में भाग लिया और इस विषय पर अपने विचारों और अनुभवों का आदान–प्रदान किया।

विस्तृत रिपोर्ट पृष्ठ 6 एवं 8 पर ....

पंजाब कार्यशालाओं के उद्घाटन सत्र।

# सम्पादक की कलम से

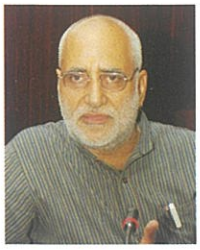

राजनीतिक इच्छाशक्ति और नेतृत्व महिलाओं के यौन और प्रजनन स्वास्थ्य तक पहुंच और सूचना, शिक्षा और सेवाओं के अधिकार में सुधार लाने के लिए मौलिक हैं। ICPD को बढ़ावा देने में सांसदों की अपने प्रतिनिधि, विधायी, बजटीय और निरीक्षण योग्य भूमिकाओं में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ICPD की 25वीं वर्षगांठ इस कार्रवाई को प्रेरित करने के लिए और राजनीतिक इच्छाशक्ति और वित्तीय प्रतिबद्धताओं को जुटाने के लिए एक अनूठा अवसर था जिसकी प्राप्ति हेतु हमें तुरंत ICPD कार्यक्रम को पूर्ण रूप से लागू करने और 2030 तक एस.डी.जी. को पूरा करने की आवश्यकता है।

1994 में 179 देशों की सरकारों द्वारा अपनाए गए ICPD कार्यक्रम ने जनसंख्या और विकास नीतियों के केंद्र में महिलाओं की जरूरतों और अधिकारों को रखने के लिए एक बहुत ही स्पष्ट संदेश जारी किया। ICPD की 25वीं वर्षगांठ ने वैश्विक समुदाय के लिए इसके ढ़ांचे पर निर्माण करने और यौन और प्रजनन स्वास्थ्य और अधिकारों के लिए एक दूरदर्शी एजेंडे को साकार करने और उन लोगों तक पहुंचने का एक अनूठा अवसर प्रस्तुत किया, जो पीछे रह गए हैं। ICPD लक्ष्यों की प्राप्ति कानूनों, नीतियों और वित्त पोषण में अंतराल को भरने के लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति पर निर्भर करेगी। केवल सांसदों के समर्थन से ही यह राजनीतिक निर्माण किया जा सकेगा।

वर्ष 2019, इस समावेशी सम्मेलन के ढाई दशक को चिह्नित करता है और इस में ICPD के हस्ताक्षरकर्ताओं ने नैरोबी, केन्या में 1994 के कार्यक्रम की कार्रवाई से संबंधित विकास की समीक्षा की और पुनर्मिलन के लिए इकट्ठा हुए। नैरोबी शिखर सम्मेलन को सरकारों द्वारा सह–अवगत कराया गया। केन्या, डेनमार्क और संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (UNFPA) और इस समावेशी मंच के प्रतिभागियों को न केवल 1994 के कार्यक्रम की कार्रवाई के पूरा नहीं हुए (unmet) लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में अपनी प्रतिबद्धताओं को साझा करने के लिए प्रोत्साहित किया, बल्कि उनकी उपलब्धि को भी उजागर किया। इस बैठक में हस्ताक्षरकर्ताओं में से एक भारत का प्रतिनिधित्व राजनीतिक नेताओं, नौकरशाहों और नागरिक समाज के सदस्यों द्वारा किया गया। भारतीय संसदीय संस्थाः जनसंख्या एवं विकास (IAPPD), जनसंख्या और विकास के मुद्दों पर जागरूकता और वकालत करने के अपने प्रयास में हमेशा सांसदों के साथ जानकारी साझा करने और प्रसार करने हेतु कार्यरत रहा है और इसके परिणामस्वरूप, इस उद्देश्य से ICPD+25 सम्मेलन की जानकारी साझा करने हेतु स्थायी समिति की बैठक 5 दिसंबर, 2019 को दिल्ली में आयोजित की गई। बैठक में राज्य सभा के उपाध्यक्ष श्री हरिवंश नारायण सिंह सहित संसद के लगभग 21 सदस्य उपस्थित थे।

ICPD25
International Conference on
Population and Development

IAPPD इस जीवन रक्षक एजेंडा के लिए अपने सहयोग को जारी रखने के लिए तत्पर है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कोई भी पीछे न रहे।

मनमोहन शर्मा
सचिव, भारतीय संसदीय संस्थानः
जनसंख्या एवं विकास

# ICPD+25 पर नैरोबी शिखर सम्मेलन

12–14 नवंबर, 2019, नैरोबी, केन्या

12–14 नवंबरए 2019 को केन्या एवं डेनमार्क की सरकारों और UNFPA द्वारा ICPD+25 पर नैरोबी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, जो एक उच्च–स्तरीय सम्मेलन था एवं जिसका उद्देश्य ICPD कार्यक्रम को लागू करने के लिए आवश्यक राजनीतिक इच्छाशक्ति और वित्तीय प्रतिबद्धताओं को जुटाना है।

शिखर सम्मेलन में निम्नलिखित पांच विषयों को संबोधित किया गया और लैंगिक समानता, युवा नेतृत्व, राजनीतिक और सामुदायिक नेतृत्व, नवाचार और डेटा, और प्रगति में तेज़ी लाने के लिए साझेदारी की शक्ति पर प्रकाश डाला गया।

- सार्वभौमिक और यौन स्वास्थ्य एवं प्रजनन स्वास्थ्य पर अधिकार सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज के एक भाग के रूप में अधिकार।
- ICPD कार्यक्रम को पूरा करने और इसके लाभ को बनाए रखने के लिए के लिए वित्तपोषण की आवश्यकता है।
- आर्थिक विकास को चलाने और स्थायी विकास को प्राप्त करने के लिए जनसांख्यिकीय विविधता को आकर्षित करना।
- लिंग आधारित हिंसा और हानिकारक प्रथाओं को समाप्त करना।
- मानवीय और नाजुक संदर्भों में भी यौन और प्रजनन स्वास्थ्य देखभाल के अधिकार को उजागर करना।

नैरोबी शिखर सम्मेलन ने सरकारों और अन्य संगठनों को स्वैच्छिक, वैश्विक प्रतिबद्धताओं की घोषणा करने के लिए एक मंच प्रदान किया जो इसकी प्रगति को गति देगा।

170 से अधिक देशों और क्षेत्रों के 8,300 से अधिक प्रतिनिधियों ने इस अद्वितीय बहु–हितधारक शिखर सम्मेलन में भाग लिया। लगभग 150 कार्यक्रम सत्र 600 से अधिक वक्ताओं के साथ आयोजित किए गए, जिनमें राज्य और सरकार के प्रमुख, रॉयल्टी, मंत्री, सांसद, संयुक्त राष्ट्र के वरिष्ठ नेतृत्व, समुदायों के नेता और निजी क्षेत्र के प्रतिनिधि, नागरिक समाज, युवा नेटवर्क आदि शामिल थे। सुश्री विप्लव ठाकुर, सांसद, और श्री मनमोहन शर्मा, सचिव, IAPPD ने इस शिखर सम्मेलन में भाग लिया।

नैरोबी शिखर सम्मेलन में, ठोस तरीकों से कैसे गरिमा और मानव अधिकारों, स्वास्थ्य और कल्याण, सुशासन, समानता और जवाबदेही की समान प्राप्ति लोगों के जीवन पर मूर्त और लाभकारी प्रभाव डालती है, पर प्रकाश डाला गया। इसने इस बात पर बल दिया कि सतत् विकास के लिए सार्वभौमिक 2030 एजेंडा के संदर्भ में जनसंख्या और विकास नीतियों और कार्यक्रमों के मार्गदर्शन में ICPD कार्यक्रम की कार्रवाई महत्वपूर्ण है।

नैरोबी शिखर सम्मेलन नैरोबी स्टेटमेंट के माध्यम से आगे के मार्ग के लिए एक स्पष्ट दिशा निर्धारित करता है, जो स्केल–अप, अभिनव और समन्वित कार्रवाई के लिए नींव प्रदान करता है। इसमें उन क्षेत्रों पर भी प्रकाश डाला गया है जहाँ हमारे कदम को सुरक्षित करने के लिए बहुत अधिक कार्रवाई की आवश्यकता है। इसके लिए सभी स्तरों पर और समाज के सभी क्षेत्रों में नए सिरे से नेतृत्व की आवश्यकता होगी।

नैरोबी शिखर सम्मेलन के दौरान हितधारकों द्वारा ICPD लक्ष्यों के समर्थन में 1,250 से अधिक प्रतिबद्धताओं के एक महत्वाकांक्षी सेट की घोषणा की गई, जो सभी के लिए यौन और प्रजनन स्वास्थ्य सुनिश्चित करने और अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए नेतृत्व–आधारित, एकीकृत निवेश के मामले का नेतृत्व करने और प्रदर्शन करने का एक अनूठा अवसर पैदा करते हैं।

श्रीमती विप्लव ठाकुर ने शिखर सम्मेलन के दौरान अपनी प्रस्तुति में SRHR मुद्दों में पुरुषों की भागीदारी के महत्व पर बल दिया।

पृष्ठ 1 से आगे ..... IAPPD की स्थायी समिति की सांसदों के साथ बैठक

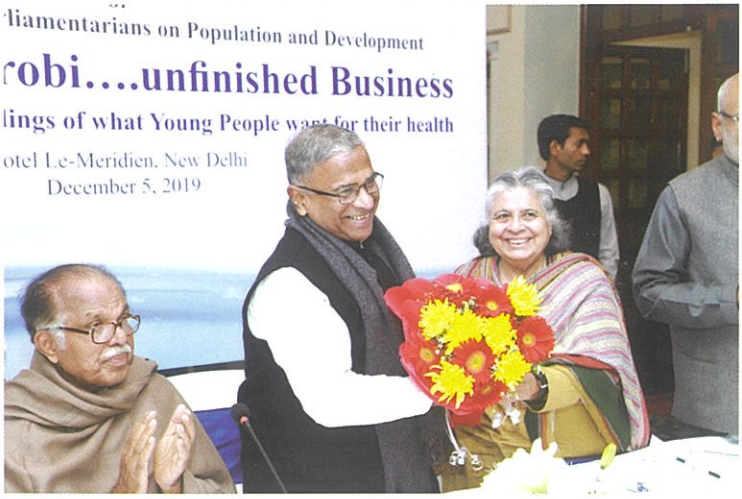


राज्यसभा के माननीय उपाध्यक्ष श्री हरिवंश नारायण सिंह का सांसद श्रीमती विप्लव ठाकुर द्वारा स्वागत किया गया।

बैठक की अध्यक्षता IAPPD की उपाध्यक्ष सुश्री विप्लव ठाकुर ने की, जिसमें उन्होंने संसद सत्र में व्यसत्ता के बावजूद सभी सांसदों का इस बैठक में भाग लेने के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने ICPD और ICPD+25 की पृष्ठभूमि एवं इसके अर्न्तगत हुए सम्मेलन की कार्यवाही के बारे में जानकारी दी जिसमें महिलाओं, उनके सशक्तीकरण, यौन और प्रजनन अधिकारों सहित महिलाओं से संबंधित मुद्दों की श्रेणी पर प्रतिभागियों, गैर–सरकारी संगठनों, सांसदों के बीच विचार–विमर्श पर ज़ोर दिया गया।

वर्ष 1994 में काहिरा में आयोजित ICPD में परिकल्पना एवं इसके उद्देश्य को साझा करते हुए अध्यक्ष प्रो. कुरियन ने अपनी टिप्पणी में लक्ष्यों की प्राप्ति और उपलब्धियों की दिशा में हस्ताक्षरकर्ता राज्यों की विफलता पर अपनी चिंता और निराशा व्यक्त की। उन्होंने कहा कि ICPD 1994 में मातृ मृत्यु दर एवं शिशु मृत्यु दर में कमीं शामिल है।

बैठक में तीन प्रस्तुतियों दी गईं और उनपर सदस्यों के बीच चर्चा हुई। प्रस्तुतियां डॉ. एस.के. सिकदर, अतिरिक्त आयुक्त, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, UNFPA के प्रतिनिधि एवं यूथबॉल अभियान द्वारा की गईं।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा की गई प्रस्तुति में ICPD+25, नैरोबी में भारत की भागीदारी के संक्षिप्त विवरण शामिल थे। प्रो. कुरियन के विचारों से सहमत होते हुए, डॉ. सिकदर ने कहा कि यह आवश्यक है कि निर्वाचित सांसदों को कार्यक्रमों के सफल कार्यान्वयन के लिए मौजूदा योजनाओं और नीतियों के बारे में जानकारी होनी चाहिए।

UNFPA द्वारा दी गई प्रस्तुति मुख्यतः जनसांख्यिकीय लाभांश सहित विभिन्न मुद्दों पर आधारित थी तथा इसमें बढ़ती युवा आबादी को संबोधित करने के लिए आवश्यक कदम शामिल थे। यह विभिन्न तंत्रों और तौर–तरीकों पर भी परिलक्षित होता है, जिसके माध्यम से सांसद जनसंख्या और विकास और आईसीपीडी के अधूरे व्यवसाय (unfinished business) से संबंधित मुद्दों के समाधान में अग्रणी भूमिका निभा सकते हैं।

यूथबॉल अभियान द्वारा की गई प्रस्तुति में लगभग 10,000 युवाओं के साथ किए गए सर्वेक्षण के निष्कर्शों और युवाओं की मांगों पर विचार किया गया। यह जनसंख्या और विकास के मुद्दों के साथ हमारे देश के युवाओं की आकांक्षाओं, चिंताओं और मांगों को दर्शाता है। उनके अध्ययन से पता चला कि युवा न केवल यौन और प्रजनन स्वास्थ्य बल्कि मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी प्रदान करने के लिए एक मज़बूत प्रणाली चाहते हैं।

जनसंख्या और विकास के मुद्दों से संबंधित प्रतिभागियों द्वारा दिए गए सुझावः

एक सांसद ने किशोरों में अपर्याप्त पोषण के बारे में आशंकाओं को साझा किया और कहा कि किशोरों और बच्चों में मधुमेह सहित जीवन शैली की बीमारियों में भारी वृद्धि हुई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ सांसदों द्वारा इन स्वास्थ्य संकटों पर चर्चा और विचार–विमर्श की तत्काल आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, सांसद ने जनसांख्यिकीय लाभांश और विविधता, आर्थिक विकास से निपटने और परिवार नियोजन में शिक्षा एवं रोजगार के अवसरों हेतु भारत की आवश्यकता का हवाला दिया।

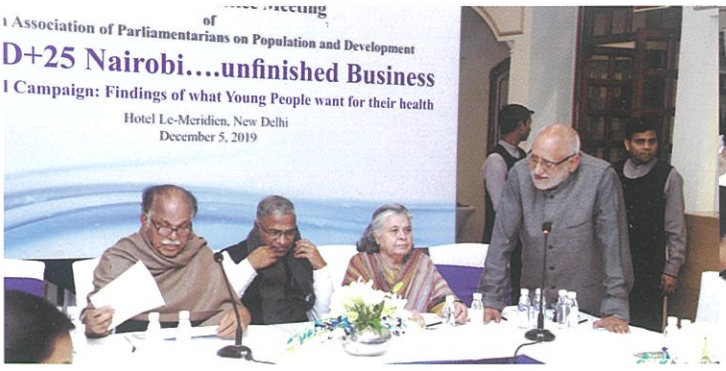

सांसदों में से एक ने समय के साथ शैक्षिक चुनौतियों और मुद्दों के प्रति अपनी आशंकाओं और चिंता को दर्शाया जिनके कारण समय के साथ सीमांत वर्गों (जाति और वर्ग के संबंध में) के बच्चों द्वारा सामना किया जा रहा है। सांसद ने यह भी कहा कि जनसंख्या में वृद्धि और गिरावट का सीधा संबंध जीवन की गुणवत्ता से है।

सांसदों में से एक ने युवाओं की आकांक्षाओं और सरकार के फैसलों के साथ–साथ न्यायपालिका के बीच हितों के टकराव के प्रति अपनी चिंता दर्शाई। उन्होंने कहा कि वर्तमान पीढ़ी मानसिक बीमारी और मासिक धर्म से संबंधित सामाजिक कलंक के विभिन्न रूपों को हटाने की इच्छा रखती है, इसलिए युवाओं और सरकार की जरूरतों और मांगों के बीच एक पुल बनाने की तत्काल आवश्यकता है। सरकार को निर्णय लेने की प्रक्रिया के दौरान युवाओं की जरूरतों और रुचि को ध्यान में रखना चाहिए।

पश्चिम बंगाल राज्य के सांसदों में से एक ने पश्चिम बंगाल की राज्य प्रायोजित योजना – कन्याश्री की उपलब्धि साझा की। उन्होने कहा कि जनसंख्या और विकास जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करते हुए सरकार को किसी विशेष मॉडल और राजनीति का अनुसरण करने के विचार को त्यागने की आवश्यकता है।

एक सांसद ने यह भी सुझाव दिया कि जनसंख्या और परिवार नियोजन मुद्दे से संबंधित एक परिवर्तन हुआ है। वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में, यह एक महत्वपूर्ण संवेदनशील राजनीतिक मुद्दा बन गया है और परिवार नियोजन की विचारधारा के प्रचार के तरीकों को देखने और फिर से जानने की आवश्यकता है।

सांसदों ने इस बात पर भी सहमति जताई कि मातृ और शिशु मृत्यु सहित जनसंख्या और विकास से जुड़े मामले न केवल गंभीर हैं बल्कि संवेदनशील भी हैं। राजनीतिक पोडियम पर इन मुद्दों को संबोधित करने की तत्काल आवश्यकता है और इसलिए इस सामाजिक मुद्दे का राजनीतिक अनुवाद करें।

जो लोग इन कार्यों से सीधे जुड़े हुए हैं और ज़मीनी स्तर पर काम करते हैं, उनके साथ संवेदना रखने और काम करना अत्यावश्यक है। इन लोगों को स्वास्थ्य और शिक्षा के महत्व से संबंधित संदेश को प्रसारित करने और लड़की पर बेटे को वरीयता देने सहित विभिन्न सामाजिक बीमारियों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए प्रशिक्षित और प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है।

जनसंख्या और विकास के मुद्दों के लिए राज्य द्वारा विभिन्न कदम उठाए गए हैं। हालांकि, तीन पहलुओं को संबोधित करने की तत्काल आवश्यकता है – सार्वभौमिक शिक्षा अर्थात 100% शिक्षा और साक्षरता, आर्थिक शक्ति में वृद्धि एवं शासन में शामिल लोगों की संवेदनशीलता।

डॉ. सिकदर, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, ने कहा कि भारत जनसंख्या प्रतिस्थापन स्तर पर पहुंच गया है न कि जनसंख्या स्थिरीकरण के। भारत की जनसंख्या वर्ष 2045–50 के बीच स्थिर हो जाएगी और यह सुनिश्चित करना अत्यावश्यक है कि जनसंख्या जनसांख्यिकीय अभिशाप में तब्दील होने के बजाय देश के लिए वरदान के रूप में कार्य करे।

बैठक में राज्य सभा के उपाध्यक्ष श्री हरिवंश नारायण सिंह सहित प्रो. पी.जे. कुरियन, राज्य सभा के पूर्व उपाध्यक्षय, श्रीमती विप्लव ठाकुर, सांसद, श्री आनंद भास्कर रापोलू, सांसद, श्री प्रदीप भट्टाचार्य, सांसद, श्री राजमोहन उन्नीथन, सांसद, श्री मुहम्मद सादिक, सांसद, प्रो. रीता बहुगुणा जोशी, सांसद, मो. नदिमुल हक, सांसद, सुश्री शांता छेत्री, सांसद, श्री जुगल किशोर शर्मा, सांसद, सुश्री डोला सेन, सांसद, श्री रिपुन बोरा, सांसद, सुश्री अमी याज्ञिक, सांसद, श्री हुसैन दलवई, सांसद, श्री जोस के. मणि, सांसद, श्री प्रदीप टम्टा, सांसद, श्री एंटो एंटनी, सांसद, श्री एन.के. प्रेमचंद्रन, सांसद, श्री रवि प्रकाश वर्मा, सांसद, और डॉ. ए. संपत, सांसद, ने भाग लिया। इसके अलावा, डॉ. एस.के. सिकदर एवं डॉ. सुमिता घोष, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, डॉ. देवेंद्र सिंह, UNFPA और सुश्री सुनीता मुखर्जी, सेवानिवृत्त UNFPA प्रतिनिधि बैठक में शामिल हुए।

# एक टी.बी. मुक्त पंजाब
# निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए कार्यशाला

20 दिसंबर, 2019, अमृतसर, पंजाब

20 दिसंबर, 2019 को जिला प्रशासन अमृतसर, पंजाब सरकार के सहयोग से IAPPD द्वारा अमृतसर, पंजाब में निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया गया।

IAPPD के सचिव श्री मनमोहन शर्मा ने अतिथियों का स्वागत किया और कार्यशाला के मुख्य उद्देश्य पर प्रकाश डाला।

कार्यशाला का उद्घाटन श्री ओ.पी. सोनी, माननीय कैबिनेट मंत्री पंजाब द्वारा किया गया और अध्यक्षता श्री दिलराज सिंह सरकारिया, अध्यक्ष, जिला परिषद ने की। कार्यशाला में जिला परिषद, नगर निगम, और ग्राम पंचायतों के पंचायती राज संस्थानों (पी.आर.आई.) के लगभग 150 सदस्यों के साथ स्वास्थ्य, शिक्षा और तपेदिक विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया।

अपने उद्घाटन भाषण में, कैबिनेट मंत्री शिक्षा और विकास श्री ओ.पी. सोनी ने कार्यशाला के आयोजन के लिए IAPPD द्वारा किए गए प्रयासों की प्रशंसा की। उन्होंने सुश्री विप्लव ठाकुर, सांसद को उनके समर्थन के लिए भी धन्यवाद दिया। उन्होंने सभा को आश्वासन दिया कि 2023 तक अमृतसर के साथ–साथ पंजाब राज्य से टीबी उन्मूलन का लक्ष्य हासिल कर लिया जाएगा। उन्होंने आगे बताया कि पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के कुशल नेतृत्व में शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण की ओर अधिक ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि टी.बी. की बीमारी और पोषण के बारे में जागरूकता की अत्यधिक आवश्यकता है।

सुश्री विप्लव ठाकुर, सांसद और उपाध्यक्ष IAPPD ने भी प्रतिभागियों को संबोधित किया।

सांसद श्री गुरजीत सिंह ओजला ने अपने संबोधन में कहा कि भारत टीबी के उन्मूलन में सफल होगा जैसाकि पोलियो उन्मूलन में किया गया था। उन्होंने नगर सेवकों से शिक्षा और स्वास्थ्य के साथ–साथ अन्य विकास गतिविधियों पर अधिक ध्यान देने का अनुरोध किया।

अमृतसर के मेयर, श्री करमजीत सिंह ने कहा कि एक कॉर्पोरेटर लगभग 20 हजार लोगों का प्रतिनिधित्व करता है और सरकार प्रत्येक जिले में टी.बी.उन्मूलन के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए इन कॉरपोरेटर्स पर ध्यान केंद्रित कर रही है। ।

डॉ. प्रभदीप कौर जौहल, सिविल सर्जन और ज़िला टी.बी. अधिकारी डॉ. नरेश चावला ने भी प्रतिभागियों को संबोधित किया।

उपरोक्त कार्यशाला के बारे में प्रतिभागियों के विचारः

- 63% प्रतिभागियों की राय थी कि कार्यशाला उत्कृष्ट थी, जिसके बाद 37% ने कहा कि यह अनुभव बहुत अच्छा था।
- इस कार्यशाला से पहले टीबी रोगों के बारे में जागरूकता के बारे में 79% प्रतिभागी जागरूक थे। केवल 17% ने बताया कि वे जागरूक नहीं थे।
- 92% प्रतिभागियों ने बताया कि टी.बी. जीन परीक्षण के परिणाम के बारे में उन्हे इस कार्यशाला में पता चला।
- भारत/पंजाब से 2025/2023 तक टीबी के उन्मूलन के सरकारी प्रयासों/कार्यक्रम के बारे में उनकी जागरूकता के बारे में पूछने पर, 96% ने बताया कि वे इस बारे में पहले से जागरूक थे।
- अधिकांश 95% प्रतिभागियों को पता था कि सरकार टीबी रोगियों को मुफ्त इलाज प्रदान कर रही है।
- कार्यशाला के बाद लगभग 88% प्रतिभागियों को पता थ कि पंजाब सरकार टीबी रोगियों को वित्तीय सहायता/मुफ्त पोषण प्रदान कर रही है।
- यह प्रश्न पूछने के दौरान कि उन्होंने इस कार्यशाला से क्या हासिल किया और वे अपने क्षेत्रों में अपने ज्ञान क उपयोग कैसे करेंगे, 58% ने बताया कि उन्हें टीबी रोग के बारे में पर्याप्त ज्ञान प्राप्त है और वे इसे अपने क्षेत्रों में लोगों के साथ साझा करेंगे।

अंत में प्रतिभागियों ने कहा कि वे अपने क्षेत्र में इस तरह के उन्मुखीकरण/संवेदीकरण टी.बी. शिविरों का आयोजन करेंगे, 75% अपने संबंधित क्षेत्रों/निर्वाचन क्षेत्रों में जागरूकता शिविर आयोजित करने और नियमित रूप से लोगों में बीमारी के बारे में संदेश फैलाने के लिए उत्सुक थे तथा वह साथ ही नियमित रूप से जांच के लिए जनता को आगे आने के लिए प्रेरित करेंगे।

## शोक संदेश

**डॉ. दिनेश अग्रवाल, IAPPD की तकनीकी सलाहकार समिति के सदस्य**

हम अत्यंत दुख के साथ यह सूचित करते हैं कि हमारे बहुत प्रिय मित्र, सहकर्मी और सदस्य, IAPPD की तकनीकी सलाहकार समिति के सदस्य डॉ. दिनेश अग्रवाल का उदयपुर (राजस्थान) में 07.12.2019 को देहावसान हो गया है।

डॉ. दिनेश अग्रवाल के दुखद और असामयिक निधन पर हमें गहरा अफसोस है। हम उनकी अनन्त यादों और IAPPD की गतिविधियों में उनके सक्रिय योगदान को कभी भुला नहीं सकते हैं। किसी भी शब्द से उनके व्यक्तित्व और काम करने की क्षमता को आंका नहीं जा सकता। डा. अग्रवाल की स्मृति में IAPPD कार्यालय में एक प्रार्थना का सभा आयोजन 10 जनवरी 2020 को किया गया। हम उनकी आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं।

# एक टी.बी. मुक्त पंजाब
# निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए कार्यशाला

23 दिसंबर, 2019, जालंधर, पंजाब

23 दिसंबर, 2019 को जिला प्रशासन, जालंधर, पंजाब सरकार के सहयोग से IAPPD द्वारा जालंधर, पंजाब में एक टी.बी. मुक्त पंजाब विषय पर जनप्रतिनिधियों के लिए एक और कार्यशाला आयोजित की गई।

IAPPD के सचिव श्री मनमोहन शर्मा ने सभी गणमान्य व्यक्तियों और प्रतिभागियों का कार्यशाला में स्वागत किया और IAPPD द्वारा की जा रही गतिविधियों के बारे में जानकारी दी।

कार्यशाला की अध्यक्षता करते हुए सांसद चौधरी संतोख सिंह ने कहा कि समाज से तपेदिक के खतरे को मिटाने के लिए ठोस और एकजुट प्रयासों की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि रोग के पूर्ण उन्मूलन के लिए बड़े पैमाने पर सामुदायिक जुड़ाव की आवश्यकता है और सभी हितधारकों को इस बीमारी के खिलाफ कार्य करना चाहिए। उन्होंने कहा कि वांछित परिणाम प्राप्त करने एवं इस रोग के उन्मूलन के लिए निर्वाचित प्रतिनिधियों सहित सभी हितधारकों की भागीदारी को और मज़बूत किया जाना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि पंजाब सरकार 2023 तक राज्य को टीबी मुक्त बनाने की दृष्टि से राज्य भर में पहले से ही व्यापक टीबी उन्मूलन कार्यक्रम चला रही है।

श्री कुलवंत सिंह, कार्यकारी उपायुक्त और नगर निगम के आयुक्त श्री दीपर्व लाकड़ा ने कहा कि टी.बी. एक रोगजनक बीमारी है और रोगियों को किसी भी कीमत पर इलाज बंद नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि ज़िला स्तर पर टी.बी. मंच बनाए गए हैं और जागरूकता सृजन अभियान चलाए जा रहे हैं।

कार्यशाला का उद्घाटन सत्र।

जालंधर की सिविल सर्जन डॉ. गुरिंदर कौर चावला ने कहा कि टी.बी. के इलाज के लिए 12 इकाइयाँ ज़िले में हैं। इन इकाइयों में निःशुल्क निदान और उपचार की सुविधा उपलब्ध है।

डॉ. राम लाल जस्सी, उपाध्यक्ष, पंजाब अनुसूचित जाति, भूमि विकास और वित्त निगम, श्रीमती. सुरजीत कौर, चेयरपर्सन जिला परिषद, सुश्री बबीता कलेर, अतिरिक्त आयुक्त, नगर निगम, डॉ. जसलीन कौर सेठी, श्री जगदीश गर्ग, श्री हरजिंदर लाडा, पार्षद, और डॉ. राजीव शर्मा, जिला टी.बी. अधिकारी इस अवसर पर उपस्थित थे।

प्रतिभागियों के विचारः

- 57% से अधिक सदस्यों की राय थी कि कार्यशाला बहुत उपयोगी थी, तथा 39% प्रतिभागियों ने इसे उत्कृष्ट बताया।
- इस कार्यशाला में भाग लेने से पहले टी.बी. रोगों के बारे में जागरूकता के बारे में 72% के बहुमत ने बताया कि वे सामान्य रूप से इस बीमारी के बारे में जानते थे लेकिन

इसकी गंभीरता को नहीं।

- दो घंटे के भीतर टी.बी. जीन परीक्षण के परिणाम के बारे में 89% प्रतिभागियों को पता नही था।
- 2025/2023 तक टीबी उन्मूलन के सरकारी प्रयासों/कार्यक्रम के बारे में जागरूकता के बारे में 61% को पहले पता नहीं था।
- टीबी मरीजों को मुफ्त इलाज मुहैया कराने वाली सरकारी सहायता के बारे में 94% के बहुमत ने बताया कि वे इस बारे में जागरूक थे।
- उनकी जागरूकता के बारे में कि पंजाब सरकार टी.बी. रोगियों को वित्तीय सहायता/पोषण की खुराक प्रदान कर रही है, 83% के बहुमत ने बताया कि उन्हें पहले जानकारी नहीं थी।
- यह सवाल पूछने पर कि उन्होंने इस कार्यशाला से क्या प्राप्त किया और वे अपने क्षेत्र/गांव में अपने ज्ञान का उपयोग कैसे करेंगे, 72% ने बताया कि उन्हें टी.बी. रोग की विषमताओं के बारे में ज्ञान प्राप्त हुआ है और वे अपने गाँव/क्षेत्र के लोगों के साथ साझा करेंगे।

अंत में महत्वपूर्ण सवाल यह था कि वे अपने क्षेत्र में टी.बी. पर इस प्रकार के शिविर का आयोजन करेंगे, लगभग 45% प्रतिनिधियों ने कहा कि वह अपने क्षेत्र में इस तरह के शिविर का आयोजन ज़िला स्वास्थ्य और टी.बी. विभाग की सहायता से करना चाहते हैं।

## *जनसंख्या और विकास पर सांसदों की 31वीं बैठक*
## ICPD25: ICPD *के अधूरे कार्यों की पूर्ति की ओर अग्रसर*

23–24 अक्टूबर, 2019, कुआलालंपुर, मलेशिया

एशियाई जनसंख्या एवं विकास संघ (APDA), जो कि जापान संसदीय जनसंख्या संघ (JPFP) के सचिवालय के रूप में कार्य करता है, द्वारा जनसंख्या और विकास पर 31वीं एशियाई सांसदों की बैठक का आयोजन 23–24 अक्टूबर, 2019 को कुआलालंपुर, मलेशिया में किया गया। इस बैठक का विषय ICPD25: ICPD के अधूरे कार्यों की पूर्ति की ओर अग्रसर होना था।

भारतीय प्रतिनिधिमंडल बैठक में भाग लेते हुए।

इस बैठक की मेज़बानी AFPPD मलेशिया द्वारा की गई तथा यह संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (UNFPA), जापान ट्रस्ट फंड (JTF) और इंटरनेशनल प्लान्ड पेरेंटहुड फेडरेशन (IPPF) द्वारा समर्थित थी। अफ्रीकी और एशियाई सांसदों की जनसंख्या और विकास पर बैठक (तंजानिया में) और अरब और एशियाई सांसदों की बैठक (मोरक्को में) इस साल APDA द्वारा आयोजित की गई बैठकों के क्रम में कुआलालंपुर में बैठक नैरोबी में होने वाले शिखर सम्मेलन तथा आईसीपीडी की 25वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित की गई थी।

एशियाई–प्रशांत और मध्य एशियाई देशों के सांसदों ने इस बैठक में भाग लिया, जिसका उद्देश्य एशियाई क्षेत्र की क्षेत्रीय विशेषताओं को दर्शाते हुए विचारों को इकट्ठा करना था। उद्घाटन सत्र में, JPFP के कार्यकारी निदेशक और AFPPD के चेयरमैन प्रो. केइजो ताकेमी ने 21 देशों के 100 से अधिक प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए उद्घाटन भाषण दिया। श्रीमती विप्लव ठाकुर, सांसद और श्री मनमोहन शर्मा, सचिव, IAPPD, ने इस बैठक में भाग लिया।

# आयुष्मान भारतः

## स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल को कैसे बदल सकते हैं

डॉ. जय प्रकाश नारायण
सदस्य, तकनीकी सलाहकार समिति, IAPPD

1 फरवरी, 2018 को, भारत के तत्कालीन वित्त मंत्री, स्वर्गीय श्री अरुण जेटली ने दुनिया की सबसे बड़ी सरकारी वित्त पोषित स्वास्थ्य कार्यक्रम आयुष्मान भारत, जिसमें 10 करोड़ परिवार या लगभग 50 करोड़ जनसंख्या शामिल है, का अनावरण किया। इस योजना में माध्यमिक और तृतीयक स्वास्थ्य सेवा के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख तक का बीमा कवर, मुख्य रूप से अस्पताल की देखभाल हेतु दिया जाएगा। आगे उन्होंने देश में 150,000 उप–केंद्रों या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को तथाकथित स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों में स्थापित करने या परिवर्तित करने की घोषणा की, जिनके अर्न्तगत मातृत्व और बाल स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, संचारी रोगों और उच्च रक्तचाप, मधुमेह और कैंसर के लिए स्क्रीनिंग तथा निवारक और उपचारात्मक सेवाओं का एक सेट प्रदान किया जाना था।

### एक गेम चेंजर

एक अग्रणी दैनिक में प्रकाशित एक लेख में, इस लेखक ने उस समय एक सवाल किया था कि क्या आयुष्मान भारत गेमचेंजर हो सकता है? उत्तर स्पष्ट रूप से हां था, बर्शते कि यह योजना सही अर्थों में लागू की गई हो। यह योजना वास्तव में समाज़ के एक बड़े वर्ग द्वारा प्रारंभिक पहचान और उपचार सेवाओं सहित स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच बढ़ाने की क्षमता रखती है जो अन्यथा ऐसा करने का जोखिम नहीं उठा सकते।

आयुष्मान भारत में वास्तव में बहुत बड़ा बदलाव करने की क्षमता है, यदि सरकार को समान माप में प्राथमिकता देने की आवश्यकता है, नीति के साथ–साथ वित्तीय संसाधन, बीमा भाग को या गरीबों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए जो द्वितीयक (secondary care) के लिए भुगतान नहीं कर सकते हैं और तृतीयक (tertiary care) देखभाल विशेष रूप से अस्पताल में भर्ती, साथ ही साथ या समान रूप से देश भर में स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों या लैब की स्थापना और उन्हें अच्छी तरह से कार्य करने के लिए सुनिश्चित करता है।

जहां आयुष्मान भारत का बीमा घटक द्वितीयक या तृतीयक देखभाल की जरूरत वाले मरीजों के इलाज के नैदानिक दृष्टिकोण के समान है, वहीं दूसरी ओर एच.डब्ल्यू.सी. एक सार्वजनिक स्वास्थ्य समुदाय का है जो बीमारी या आबादी या समुदाय के बीच स्वास्थ्य को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है।

इसके समर्थन में कुछ कारण यहां दिए गए हैं:
एक, कार्यात्मक एच.डब्ल्यू.सी. की स्थापना देश में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल या पी.एच.सी. को मज़बूत करने का एक अभूतपूर्व अवसर प्रदान करती है जो कि जहां वे रहते हैं, वहां के लोगों को स्थायी रूप से प्रदान की जाने वाली गुणवत्ता की आवश्यक स्वास्थ्य देखभाल है।

स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच और गुणवत्ता पर ध्यान देने के साथ, ऐसा दृष्टिकोण सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज या यू.एच.सी. को प्राप्त करने में मदद कर सकता है जैसी कि सितंबर 2019 में न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र की उच्च स्तरीय बैठक में वकालत की गई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने प्लेनरी में बोलते हुए कहा था कि "स्वास्थ्य हर एक का अधिकार है। यह सुनिश्चित करना मेरी सरकार की जिम्मेदारी है"।

### रोकथाम इलाज से बेहतर है

दूसरा, स्वास्थ्य को बढ़ावा देने, बीमारी की रोकथाम और शुरुआती पहचान पर ध्यान केंद्रित करके, एच.डब्ल्यू.सी. लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार कर सकता है और उन्हें पहले स्थान पर बीमार होने से रोक सकता है। यह न केवल स्वास्थ्य पर बाहर के जेब खर्च को कम करेगा जो 65% दुनिया में सबसे अधिक है, बल्कि रोगियों के माध्यमिक और तृतीयक देखभाल सुविधाओं के प्रवाह को भी कम करता है। वर्तमान में स्वास्थ्य देखभाल की उच्च लागत के कारण भारत में 60 मिलियन लोग गरीबी में फंस गए हैं जिससे वे बच नहीं पा रहे हैं।

तीसरा, अत्यधिक लागत प्रभावी रणनीति और गरीबी में कमी के लिए एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में, एच.डब्ल्यू.सी. अल्प संसाधनों का एक अच्छा निवेश है जो अस्पताल में प्रवेश को सीमित करेगा और लाखों रुपये बचाएगा, जो अन्यथा उच्च तकनीकी निदान और चिकित्सा/शल्य चिकित्सा पर खर्च किए जाते थे।

इसलिए, यह सबसे कमज़ोर और दुर्गम क्षेत्रों में प्राथमिकता के साथ एच.डब्ल्यू.सी. में अधिक निवेश करने के लिए बहुत

पृष्ठ 11 पर जारी .....

# फेफड़े के स्वास्थ्य पर 50वां केंद्रीय विश्व सम्मेलन

अक्टूबर 30–नवंबर 2, 2019, हैदराबाद, भारत

हैदराबाद, भारत में 30 अक्टूबर से 2 नवंबर, 2019 के मध्य अंतर्राष्ट्रीय संघ द्वारा क्षय रोग और फेफड़े की बीमारी (संघ) के खिलाफ आयोजित 50वें डब्ल्यू.एच.ओ. एंड टी.बी. रणनीति शिखर सम्मेलन के लिए 33 देशों, भागीदारों और नागरिक समाज के 200 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

इस वार्षिक बैठक में टी.बी. समाप्त करने की दिशा में वैश्विक और राष्ट्रीय प्रगति की समीक्षा करने के लिए नागरिक समाज सहित अन्य हितधारकों के साथ उच्च प्राथमिकता वाले देशों के राष्ट्रीय तपेदिक कार्यक्रम (NTP) प्रबंधकों को एक साथ लाया गया। इस बैठक ने देशों और हितधारकों के लिए एक महत्वपूर्ण ज्ञान साझा करने का मंच भी प्रदान किया।

भारत के माननीय उपराष्ट्रपति, श्री एम. वेंकैया नायडू, इस अवसर पर मुख्य अतिथि थे तथा उन्होंने 30 अक्टूबर, 2019 को इस सम्मेलन का उद्घाटन किया। सम्मेलन का विषय आपातकाल को समाप्त करना था।

डॉ. रेन मिंगहुई, डब्ल्यू.एच.ओ. के सहायक महानिदेशक ने इस अवसर पर मुख्य भाषण दिया। अन्य वक्ताओं में फिल्म और टेलीविजन अभिनेत्री क्लेयर फोर्लानी शामिल थीं, जिन्होंने द यूनियन और तेलंगाना राज्य के वरिष्ठ प्रतिनिधियों के लिए राजदूत के रूप में एक भूमिका स्वीकार की।

इस वर्ष का शिखर सम्मेलन कई शीर्ष मुद्दों पर केंद्रित था जैसेकि दवा प्रतिरोधी टी.बी. उपचार और टी.बी रोकथाम उपचार के लिए डब्ल्यू.एच.ओ.–अनुशासित दिशा निर्देशों को स्केल–अप करना तथा उपयोग हेतु डब्ल्यू.एच.ओ. मल्टी–सेक्टोरल अकाउंटबिलिटी फ्रेमवर्क का टी.बी. के लिए अनुकूलन और कार्यान्वयन, और टी.बी. रोगियों तक पहुंचना।

भारत के माननीय उपराष्ट्रपति, श्री. एम. वेंकैया नायडू ने सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री श्री. अश्विनी कुमार चौबे भी उपस्थित थे।

बैठक में देशों ने प्रगति और अभिनव दृष्टिकोणों के साथ–साथ इंटरैएक्टिव समूह और पूर्ण सत्र में सन् 2020 में किए जाने वाले तत्काल कार्यों पर चर्चा की। उद्घाटन और समापन सत्रों में नागरिक समाज और युवाओं के प्रतिनिधि एन.टी.पी. नेता शामिल हुए। डब्ल्यू.एच.ओ. की Find-Treat-All # EndTB पहल पर एक विशेष सत्र, ग्लोबल फंड और स्टॉप टीबी पार्टनरशिप भी आयोजित किया गया।

पृष्ठ 10 से आगे ..... *आयुष्मान भारत*

अधिक समझ में आता है, जहां स्वास्थ्य सेवाएं सबसे अच्छी स्थिति में हैं। इसके कार्यों को ठीक से सुनिश्चित करने के लिए, उन्हें संसाधनों के अधिक से अधिक आवंटन की आवश्यकता होगी, जिसका उपयोग स्वास्थ्य सेवाओं के वितरण के लिए महत्वपूर्ण है। आपूर्ति सुनिश्चित करना और स्वास्थ्य सूचना प्रणाली को मज़बूत करना भी आवश्यक है जो ज़िला स्तर और नीचे योजना बनाने में मदद कर सकता है।

अंत में, केवल जिला स्वास्थ्य प्रणाली को मज़बूत करके, हम गांधीजी के स्वस्थ भारत के सपने को साकार करने की आशा कर सकते हैं क्योंकि भारत का भविष्य इसके गांवों में निहित है और इस प्रकार ग्रामीण और परिधीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए ग्राम स्वच्छता और प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

सांसदों और पंचायती राज संस्थानों की जिम्मेदारी है कि वे यह सुनिश्चित करें कि उनके संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में स्थापित किए जा रहे स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र अच्छी तरह से काम करें और हर किसी को हर जगह दक्षता और टिकाऊ तरीके से गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करें!

# 2020 परिवार नियोजन से परेः युवा परिप्रेक्ष्य - एक राष्ट्रीय परामर्श

15 अक्टूबर, 2019, नई दिल्ली

परामर्श के उद्देश्य 2020 परिवार नियोजन से परे, एक अधिकार–आधारित, युवा–केंद्रित लेंस से परिवार नियोजन के राष्ट्रीय प्रवचन को फिर से परिभाषित करने पर विचार–विमर्श करना था। युवा लोगों द्वारा उनकी आवश्यकताओं, अधिकारों और परिवार और अन्य एस.आर.एच. मुद्दों के बारे में जानकारी बढ़ाने के लिए 'यूथ डायलॉग' का एक देशव्यापी अभियान प्रस्तुत करना और युवा लोगों के लिए FP सहित SRH की पहुंच, विकल्प और गुणवत्ता को अधिकतम करने के लिए बहु–हितधारक जुड़ाव बनाना इस परामर्श का उद्देश्य था।

परामर्श का उद्घाटन केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने किया। सुश्री मीना बर्लिंग, बाहरी संबंध निदेशक, आई.पी.पी.एफ., सुश्री वंदना गुरनानी, संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य मंत्रालय और श्री मनोज झालानी, स्वास्थ्य मंत्रालय भी इस अवसर पर उपस्थित थे। IAPPD के सचिव श्री मनमोहन शर्मा ने भी इस परामर्श में भाग लिया।

SRHR पर युवा आवाज पर सत्र में राय, अपेक्षाएँ और आगे का रास्ता, आर.एच. सेवा वितरण के लिए अधिकार आधारित दृष्टिकोण और परामर्श के दौरान युवा लोगों के लिए एफ.पी. पसंद, पहुंच और गुणवत्ता का विस्तार किया गया।

इस परामर्श ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, विभिन्न सरकारी एजेंसियों, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज और इसके जीवंत स्वयंसेवकों के महत्वपूर्ण हितधारकों को विचार विमर्श का अवसर प्रदान किया। इस परामर्श ने सभी हितधारकों के लिए मौजूदा रुझानों का विश्लेषण करने, नवीनतम जनसांख्यिकीय, नैदानिक और क्षेत्र–आधारित सबूतों की जांच करने और भारत में युवा लोगों के लिए एफ.पी. और एस.आर.एच.आर. कार्यक्रमों के प्रभाव को अधिकतम करने के लिए एक साझा मंच प्रदान किया।

जनसंदेश

संपादक

मनमोहन शर्मा

जनसंदेश एक त्रैमासिक पत्रिका है

भारतीय संसदीय संस्थान – जनसंख्या एवं विकास

(संयुक्त राष्ट्र के साथ विशेष परामर्शदाता स्थिति)

1/6, सीरा इन्स्टीट्यूशनल एरिया, खेल गॉव मार्ग, नई दिल्ली–110049

दूरभाषः 011–4165661/67/68/76, फैक्सः 011–41656660

ई.मेल: iappd@airtelmail.in, वेब साईटः www.iappd.org


Asha Enterprises: 9811854631